



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 8 सितम्बर, 1986/17 चात्रपद, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

PERSONNEL DEPARTMENT
APPOINTMENT-I

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th August, 1986

No. Per. (A-I)-B (2)-3/85.—Under rule 15 of the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following candidate, who competed successfully the Himachal Pradesh Administrative Service etc. competitive examination held in 1985, to the Himachal Pradesh Administrative Service on probation with effect from the date of his joining as such:—

Sr. No. Name and address of the candidate

1 Shri Kamal Sharma, Government High School, Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh-172 029.

2. Shri Kamal Sharma shall furnish a written acceptance of appointment offered to him immediately on the receipt of this appointment letter to the Under Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, failing which the offer of appointment shall be treated as cancelled.

3. In case of acceptance of appointment, Shri Kamal Sharma shall report for duty to the Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Fair Lawns, Shimla-171012, immediately for undergoing foundational course.

4. This offer of appointment is subject to the provisions of the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, as amended from time to time.

By order,
P. K. MATTOO,
Chief Secretary.

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 7th August, 1986

No. Home-II(B)15-6/79.—In exercise of the powers vested in him under section 7, sub-section (2) of the Criminal Law (Amendment) Act, 1952, and in supersession of all previous notifications in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that where there are more than one Special Judges in a Sessions Division, powers under section 6(1) of the said Act shall be exercised within the Sessions Division by that Special Judge who is the Sessions Judge for that Division.

A. K. MOHAPATRA,
Secretary.

शिमला-2, 7 अगस्त, 1986

संख्या गृह (ए)-7(जी)-19/75-भाग-III.—हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या गृह (ए)-7 (जी)-19/75-III दिनांक 22-2-1986, जो कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) दिनांक 29-3-1986 के अंक में प्रकाशित हुई थी के सन्दर्भ में तथा मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आर्टिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवां अधिनियम) की धारा 9 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर में हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या गृह (ए)-7(जी)-19/75-II दिनांक 7-8-1981 जो कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण), दिनांक 29 अगस्त, 1981 के अंक में प्रकाशित हुई थी, के द्वारा पूर्व परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग तथा आर्टिलरी अभ्यास को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं :—

अगस्त, 1986

सितम्बर, 1986

दिसम्बर, 1986

7 अगस्त, 1986	1 से 2 सितम्बर, 1986 तक	10 दिसम्बर, 1986
9 अगस्त, 1986	4 से 6 सितम्बर, 1986 तक	18 से 20 दिसम्बर, 1986 तक
11 से 12 अगस्त, 1986 तक	8 से 9 सितम्बर, 1986 तक	22 से 23 दिसम्बर, 1986 तक
14 अगस्त, 1986	11 से 13 सितम्बर, 1986 तक	
16 अगस्त, 1986	15 से 16 सितम्बर, 1986 तक	
18 से 19 अगस्त, 1986 तक	18 से 20 सितम्बर, 1986 तक	
21 से 23 अगस्त, 1986 तक	22 सितम्बर, 1986	
25 से 26 अगस्त, 1986 तक	25 से 27 सितम्बर, 1986 तक	
28 से 30 अगस्त, 1986 तक	29 से 30 सितम्बर, 1986 तक	

जनवरी, 1987

फरवरी, 1987

1 से 3 जनवरी, 1987 तक
5 से 6 जनवरी, 1987 तक
8 से 10 जनवरी, 1987 तक
12 से 13 जनवरी, 1987 तक
15 से 17 जनवरी, 1987 तक
19 से 20 जनवरी, 1987 तक
22 से 24 जनवरी, 1987 तक
27 जनवरी, 1987
29 से 31 जनवरी, 1987 तक

2 से 3 फरवरी, 1987 तक
5 से 7 फरवरी, 1987 तक
9 से 10 फरवरी, 1987 तक
12 से 14 फरवरी, 1987 तक
16 से 17 फरवरी, 1987 तक
19 से 21 फरवरी, 1987 तक
23 से 24 फरवरी, 1987 तक

आदेश द्वारा.

ए०के० मोहापात्रा

आयुक्त एवं सचिव (गृह)।

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 17 मई, 1985

संख्या 4-6/82-श्रम-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 के सभी उपबन्धों को, अधिसूचित क्षेत्र समिति परवानू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र को तुरन्त लागू करते हैं।

आदेश द्वारा,

ओ० पी० यादव,

आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of this Government Notification No. 4-6/82-Shram-II, dated 17-5-1985, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

Shimla-2, the 17th May, 1985

No. 4-6/82-Shram-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the H.P. Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (Act No. 10 of 1970), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to apply all the provisions of the H.P. Shops and Commercial Establishments Act, 1969 to the local area of Notified Area Committee, Parwanoo, District Solan (H.P.), with immediate effect.

By order,

O. P. YADAV,

Commissioner-cum-Secretary.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनायें

शिमला-171002, 30 जुलाई, 1986

संख्या पी०बी०डब्ल्यू (बी एण्ड आर) (बी) 26(33)/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश टाउन एवं कण्ट्री प्लानिंग ऐक्ट, 1977 (1977 का 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए डलहौजी योजना क्षेत्र का गठन करते हैं और निम्नलिखित रूप में इसका सीमांकन करते हैं:—

विनिर्देश

उत्तर: }	
पूर्व: }	डलहौजी हदबस्त संख्या 422 की सीमा तक।
दक्षिण: }	
पश्चिम: }	बनीखेत हदबस्त संख्या 98 की सीमा तक।

डलहौजी योजना क्षेत्र

डलहौजी योजना क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित पूर्ण राजस्व उपनियम होंगे:—

1. डलहौजी (नगर पालिका) छावनी को छोड़कर हदबस्त सं० 422
2. बनीखेत हदबस्त सं० 98।

[Authorised English text of Notification No. PBW(B&R)(B)-26(33)/86, dated 30-7-1986 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

Shimla-171002, the 30th July, 1986

No. PBW(B&R)(B)26(33)/86.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the Dalhousie Planning Area for the purpose of the aforesaid Act and to define its limits as under:—

SPECIFICATION

North: }	
East: }	Upto the boundary of Dalhousie Hadbast No. 422.
South: }	
West: }	Upto the boundary of Banikhet Hadbast No. 98.

DALHOUSIE PLANNING AREA

Dalhousie Planning Area shall include following complete revenue settlements:—

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dalhousie (M.C.) excluding cantonment | Hadbast No. 422 |
| 2. Banikhet | Hadbast No. 98. |

शिमला-171002, 30 जुलाई, 1986

संख्या पी 0 बी 0 डब्ल्यू (बी 0 एण्ड आर 0 (बी)-26(33)/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश टाउन एवं कण्ट्री प्लानिंग एक्ट, 1977 (1977 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1986 के अगस्त मास के प्रथम दिन को ऐसे दिन के रूप में नियत करते हैं जिसको उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्ध नीचे यथा वर्णित डलहौजी योजना क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे:—

विनिर्देश

उत्तर: }	
पूर्व: }	डलहौजी हदबस्त संख्या 422 की सीमा तक।
दक्षिण: }	

पश्चिम: बनीखेत हदबस्त संख्या 98 की सीमा तक।

डलहौजी योजना क्षेत्र

* डलहौजी योजना क्षेत्र में निम्नलिखित पूर्ण राजस्व वस्तियां शामिल हैं:—

1. डलहौजी (नगर पालिका) कैंट को छोड़ कर हदबस्त सं० 422.
2. बनीखेत हदबस्त सं० 98.

[*Authorised English text of notification No. PBW(B&R)(B)26(33)/86, dated 30-7-1986 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.*]

Shimla-171002, the 30th July, 1986

No. PBW(B&R)(B)26(33)/86.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st day of August, 1986 as the day on which the provisions of the aforesaid Act shall come into force in the Dalhousie Planning Area as described in the specification below:—

SPECIFICATION

North:	}	Upto the boundary of Dalhousie Hadbast No. 422.
East:		
South:		
West:		

DALHOUSIE PLANNING AREA

Dalhousie Planning Area shall include following complete revenue settlements:—

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dalhousie (M.C.) excluding cantonment | Hadbast No. 422 |
| 2. Banikhet | Hadbast No. 98. |

By order,
B. B. TANDON,
Commissioner-cum-Secretary.

DIRECTORATE OF CONSOLIDATION OF HOLDINGS

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th August, 1986

No. Rev. (CH) P (50)/80.—In the interest of general public and for the purpose of better cultivation of land, I, H. S. Atwal, Director, Consolidation of Holdings, Himachal Pradesh in exercise of the powers under sub-section (1) and (2) of section 14 of the Himachal Pradesh Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1971 as delegated to me *vide* notification No. 9-1/73-Rev. II, dated 4th May, 1971 hereby declare the intention of the Himachal

Pradesh Government to make the Scheme for Consolidation of Holdings for the under-mentioned estates:—

S. No.	Name of Tika	Name of Mauza	H.B. No.	Area (Acres)	Tehsil	District
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mahadev	Mahadev	10	401	Sundernagar	Mandi
2.	Ghamol	-do-	14	253	-do-	-do-

H. S. ATWAL,
Director.

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

बिलासपुर, 14 अगस्त, 1986

क्रमांक आपूर्ति शाखा/85-471 3-4767.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक आपूर्ति शाखा/86-3949 से 4005 दिनांक 26-6-86 के सन्दर्भ में, जे० आर० गाजटा, जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश जमाखोरी मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई) के अन्तर्गत प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश करता हूँ कि उक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य अगले दो मास तक सारे बिलासपुर जिला में जारी रहेंगे।

जे० आर० गाजटा,
जिला दण्डाधिकारी,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT HAMIRPUR, DISTRICT HAMIRPUR

NOTIFICATION

Hamirpur, the 14th August, 1986

No. Supply Branch/86-5052.—In exercise of the powers conferred upon me under sub-clause (1) (d) and (e) of clause 3 of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Ashis Dev, District Magistrate, Hamirpur do hereby fix the maximum consumers price of the L.P.G. cylinder and cooliage from ex-godown (Salasi) of Hamirpur Gas Service, Main Bazar, Hamirpur (Himachal Pradesh) as under:—

1. (1) If the delivery is effected by the Gas Agency at consumers door steps Rs. 69/- per cylinder.

(2) In case, the delivery is taken by the consumers from ex-godown Rs. 65.59 paisa per cylinder.

2. The dealer of the L.P.G. Agency will issue cash-memo for all the transactions. The dealer should also indicate consumer No., address and amount charged in the cash-memo.

3. The L.P.G. Agency holder shall display daily stock position, sale rate, ex-godown and at door steps separately of the consumers at the conspicuous place at business premises.

4. The L.P.G. Agency holder shall not pressurise the consumers for the purchase of accessories at the time of giving new connection. The release of new L.P.G. connections to the consumers living within the areas of jurisdiction of the Agency shall be made strictly on the first come first serve basis and only against valid ration cards. The register in respect of the release of new connections shall be maintained in the following proforma:—

Sr. No.	Name and address of the consumer	Regd. No. and date	Date of depositing security and consumers No. allotted	Date of release of new connection
1	2	3	4	5

5. The L.P.G. dealer shall display every day the serial No. of booking from to for refill and filled cylinders are available in the stock with him. All the consumers within the area of jurisdiction of this Agency, of serial Nos. shall become eligible consumers for refill supplies.

6. The register regarding daily delivery of L.P.G. shall be in the following manner:—

Sr. No.	Consumer No.	Cash-memo No. and date	Date of delivery	Name of Coolie & No.	Remarks
1	2	3	4	5	6

The above records shall be maintained in addition to the records already prescribed by the Oil Companies or provided under any other law for the time being in force.

7. The L.P.G. Agency holder shall submit a weekly/monthly returns in the following proforma to the District Food and Supplies Controller, Hamirpur:—

Opening Balance of L.P.G. refills	L.P.G. refills received during the week/month	Total	Issue	Balance
1	2	3	4	5

This notification will remain in force for 30 days from the date of publication in the Official Gazette.

ASHIS DEV,
District Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur.

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन

कार्यालय आदेश

नाहन, 4 अगस्त, 1986

संख्या पी० एस०-3-मिस० 12/63-3010-13.—यतः ग्राम सभा देवकापुड़ला, विकास खण्ड नाहन ने अपने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 19-7-1986 द्वारा बहुमत से निर्णय लिया है कि ग्राम सभा देवकापुड़ला का मुख्यावास देवकापुड़ला न हो कर ग्राम जामली में होना चाहिए क्योंकि यह ग्राम सभा देवकापुड़ला का केन्द्रीय स्थान बनता है ;

और चूंकि विकास खण्ड अधिकारी, नाहन ने अपने पत्र संख्या डी०बी०एन-पंच/86-1664, दिनांक 25 जुलाई, 1986 द्वारा सिफारिश की है कि ग्राम सभा देवकापुड़ला का मुख्यावास ग्राम जामली में निर्धारित किया जाये ।

अतः मैं, बी० एस० नैण्टा, उपायुक्त, जिला सिरमौर उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 10 (2) में प्राप्त हैं ग्राम सभा देवकापुड़ला के उक्त प्रस्ताव तथा विकास खण्ड अधिकारी, नाहन की सिफारिश के आधार पर ग्राम सभा देवकापुड़ला का मुख्यावास देवकापुड़ला से बदल कर ग्राम जामली में निर्धारित करने के आदेश देता हूँ ।

बी० एस० नैण्टा,
उपायुक्त, सिरमौर नाहन ।

मत्स्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 जुलाई, 1986

नं० फिश-ए (3) 1/77-वोल्यूम-1.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश फिशरी ऐक्ट, 1976 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की अधिसूचना सं० फिश-ए (3) 1/77 तारीख 15 नवम्बर, 1979 के साथ पठित तारीख 16 फरवरी, 1980 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित हिमाचल प्रदेश फिशरी रूल्स, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (5) के अधीन अपेक्षित है, प्रस्तावित नियमों का संशोधन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके कि उन से प्रभावित होने की संभावना है । इन नियमों के संशोधन पर आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख 30 दिन की अवधि के भीतर, सचिव मत्स्य, हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे जा सकेंगे । इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, प्रस्तावित संशोधन की वास्तव प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर, यदि कोई हों, सरकार इसे अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार करेगी :

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Fisheries (Amendment) Rules, 1986.

(2) These rules shall come into force at once.

2. Amendment of schedule.—Against serial No. 4 at column No. 6 of the revised schedule appended to the Himachal Pradesh Fisheries Rules, 1979, for the figure and sign “15%” the figure and sign “12½%” shall be substituted.

By order,
B. C. NEGI,
Additional Chief Secretary-cum-Secretary.

[Authoritative English text of notification No. FSH.A(3) 1/77-Vol-I, dated 23-7-1986 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

Shimla-2, the 23rd July, 1986

No. FSH.A(3)1/77-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Fisheries Act, 1976, the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following amendment in the Himachal Pradesh Fisheries Rules, 1979 notified *vide* Government notification No. Fsh. A(3)1/77, dated 15th November, 1979 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, Extra-ordinary dated 16th February, 1980. The proposed amendment is hereby published as required under sub-section (5) of section 3 of the said Act for the information of all the persons likely to be affected thereby and objections and suggestions, if any, from such persons should be addressed to the Secretary (Fisheries) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla within 30 days from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh Extra-ordinary after which the amendment objections and suggestions, if any, so received within the stipulated period shall be taken into consideration before finalizing the proposed amendment:—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Fisheries (Amendment) Rules, 1986.

(2) These rules shall come in to force at once.

2. Amendment of schedule.—Against serial No. 4 at column No. 6 of the revised schedule appended to the H.P. Fisheries Rules, 1979, for the figure and sign “15%” the figure and sign “12½%” shall be substituted.

By order,
B. C. NEGI,
Additional Chief Secretary-cum-Secretary.

DIRECTORATE OF CO-OPERATION

ORDER

Shimla-2, the 8th July, 1986

No. 5-65/80-Co-op. (C&M)-II.—In exercise of the powers vested in me under rule 56 (1) of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Rules, 1971, and in supersession of order of even number dated 29-6-1985, I, Yogesh Khanna, Registrar, Co-operative Societies, Himachal Pradesh hereby frame Rules relating to the terms of employment and working conditions of the

Secretaries of Primary Agricultural Credit Societies functioning in Himachal Pradesh as annexed with immediate effect.

YOGESH KHANNA,
Registrar, Co-operative Societies.

RULES RELATING TO THE TERMS OF EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS OF THE SECRETARIES OF PRIMARY AGRICULTURAL CREDIT SOCIETIES

1. These rules may be called the Primary Agricultural Credit Societies Secretaries (Terms of Employment & Working Conditions) Rules.

2. These rules shall come into force from such date as the Registrar, Co-operative Societies, Himachal Pradesh may specify in this behalf.

3. These rules shall apply to all the Secretaries of the Primary Agricultural Credit Societies in service on the date the rules come into force and who may be taken or appointed by the Societies after the said date.

4. Definitions:

- (a) In these Rules unless the context otherwise requires 'Registrar' means Registrar, Co-operative Societies, Himachal Pradesh or any other officer to whom powers of Registrar has been delegated.
- (b) "Society" means Primary Agricultural Credit Society which term includes Multi-purpose Service and Thrift and Credit Societies functioning in rural areas.
- (c) 'Year' means co-operative year commencing from 1st July and ending on 30th June every year.
- (d) 'President' means the President of the Society and includes the Vice-President/Acting President.
- (e) 'Committee' means the Managing Committee of the Society.

5. Pay scales

- (a) The scales of pay of Secretaries shall be as under:—

<i>Class of Society</i>	<i>Pay scales</i>
'A'	Rs. 800-25-1500
'B'	Rs. 600-20-1000
'C'	Rs. 400-15-700
'D'	Rs. 300-10-450

These scales will be inclusive of all allowances i.e. the pay drawn in this scale will be the consolidated pay.

(b) The classification of Societies as stated above into 'A', 'B', 'C', and 'D' shall be on the basis of (i) loaning business which will include Short and Medium Term loans issued during the year, (ii) deposit mobilisation at the end of the year, (iii) distribution of consumer articles and fertilizer activities undertaken during the year, and (iv) Recovery performance during the year as given below:

CLASS: CLASSIFICATION OF SOCIETIES ACCORDING TO THE INTEGRATED NORMS

'A' Societies having (i) Advancement of ST/MT loans to their members to the extent of Rs. 3.00 lakhs and above during the year.

(ii) Societies which have mobilised deposits to the tune of above Rs.1.80 lakhs at the end of the year. (iii) Societies which have undertaken activities of distribution of consumer articles and fertilizer of Rs. 3.00 lakhs and above during the year. (iv) Societies having effected recoveries to the extent of 80% and above of the demand during the year.

'B' (i) Advancement of ST/MT loans to their members between Rs. 2.00 lakhs and Rs. 3.00 lakhs during year. (ii) Societies which have mobilised deposits to the tune of Rs. 1.20 lakhs and below Rs. 1.80 lakhs at the end of the year. (iii) Societies which have undertaken activities of distribution of consumer articles and fertilizer above Rs. 2.00 lakhs and below Rs. 3.00 lakhs during the year. (iv) Societies having effected recoveries to the extent of 60% and below 80% of the demand during the year.

'C' (i) Advancement of ST/MT loans to their members between Rs. 1.00 lakhs and below Rs. 2.00 lakhs during the year. (ii) Societies which have mobilised deposits between Rs. 0.60 lakhs and below Rs. 1.20 lakhs at the end of the year. (iii) Societies which have undertaken activities of distribution of consumer articles and fertilizer above Rs. 1.00 lakh and below Rs. 2.00 lakhs during the year. (iv) Societies having effected recoveries of above 40% and below 60% of the demand during the year.

'D' (i) Advancement of ST/MT loans to their members below Rs. 1.00 lakhs during the year. (ii) Societies which have mobilised deposits to the extent of Rs. 0.60 lakh and below at the end of the year. (iii) Societies which have undertaken activities of distribution of consumer articles and fertilizer below Rs. 1.00 lakhs during the year. (iv) Societies having effected recoveries to the extent of 40% of the demand during the year.

A Society for being classified in a particular category will have to satisfy all the four criteria fixed for that class. Classification will be done every year in the month of July on the basis of working of the society during the last year.

(ii) If the implementation of scales of pay prescribed in these Rules effects adversely any Secretary of a Society exemption can be sought from the Registrar, Co-operative Societies, who will consider the working results of the Society while considering such exemption.

(iii) In case the management feels that keeping in view the resource position of the Society, it would not be able to pay the scales mentioned above, it may obtain the permission of the Registrar to pay such scales as may be appropriate.

(iv) The following classes of Societies shall not give the above scales of pay to the Secretaries employed by them :—

(a) Societies which pre dormant and not undertaking any business.

(b) Societies undertaking solely the work of sugar distribution.

A society for being classified in a particular category will have to satisfy all the four criterias fixed for that class. Classification will be done every year in the month of July on the basis of the working of the Society. .

(c) A society falling in one of the class indicated in clause (b), if it improves its performance during the time and attains the higher class, the Secretary of the said Society shall be eligible for the scale of pay fixed for that higher class.

In case, the society does not sustain its classification on the basis of its annual performance and falls below the said classification, the Secretary of the said Society shall be eligible for the pay scales of the lower class and his pay shall be fixed at the maximum in that scale.

- (d) The pay of the Secretary shall be fixed in the scales mentioned above on the basis of its classification with effect from the date to be specified by the Registrar. In case the existing pay of the Secretary is higher than the scale fixed for that class of a Society in which the Society falls, the difference of pay shall be treated as personal pay which shall be adjusted in the further increments earned by the Secretary.
 - (e) The Secretary of the Society shall furnish security according to the form and standard prescribed by the Registrar from time to time.
 - (f) The untrained Secretary already in the service of a Society will have to undergo the training within two years of the enforcement of these rules. The Society will obtain a bond before sponsoring him for training for serving the Society for five years after training. It will be obligatory on the part of the Society to take him back after he has been imparted training. Exemption from bond may be given in exceptional cases by the Registrar, Co-operative Society.
 - (g) If the Secretary resigns before expiry of the period of his bond, he shall be required to pay to the Society an amount equivalent to his pay for the un-expired period of his bond.
6. The vacancies shall be filled by direct recruitment through calling applications from all the eligible candidates residing in the area of operation of such Society. Notice for calling the applications indicating basic qualifications, age and other qualifications required shall be pasted on the notice board in the office of the Society.
7. The qualification laid down for the post of Secretary shall be as under:—
- (a) (i) *Candidates belonging to the general categories.* At least second division in Matric/Higher Secondary or equivalent from a recognised University/Board.
 - (ii) *Candidates belonging to reserve categories such as Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes.* At least Matriculate/Higher Secondary with minimum 45% marks or equivalent from a recognised University/Board.
 - (iii) Training in Co-operation for four or six months at a Co-operative Training Centre will be a desirable qualification.
 - (b) No person shall be eligible for appointment unless, he is above 18 years and below 32 years of age on the date of application. Provided further that there shall be relaxation in age by five years to the candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Ex-servicemen/Handicapped persons.
 - (c) Preference shall be given to the candidates who have undergone Co-operative Training for four or six months at a Co-operative Training Centre.
8. No person shall be appointed in the service unless he produces from a Government Medical Officer a certificate about his physical and mental fitness.
9. No person shall be appointed in the service unless his antecedents has been certified to the satisfaction of the Society.
10. An employee on his appointment shall have to furnish a statement of his wealth and that of his dependents and a statement of debt owned by him.
11. The appointment shall initially be on probation for a period of two years. During the probation period he shall be eligible for the basic pay only and he will become eligible for increments only on satisfactory completion of his probation and subject to the provision of rule 10. His regular appointment shall be considered on completion of the probation period.

12. Selection Committee:

The following shall constitute the Selection Committee for the selection of a Secretary:—

- (a) Chairman of the Society.
- (b) Inspector Co-operative Societies of the circle.
- (c) One member of the managing committee of the Society.

13. The marks allotted for the interview shall be as under:—

Qualification;	(i) (a) Graduate	2	5
	(b) Post-graduate	3	
Experience :	(ii) One mark for every one year		15
	(iii) Training in Co-operation		15
	(iv) Interview		15
			<hr/> 50

14. Increments:

Annual increment under the grade shall be deemed to be due *w.e.f.* first of the month when the Secretary has completed one year provided the Society is in profit which profit shall be on the basis of the annual audit of the society.

If any Secretary reaches the maximum of the scales of pay allowed for the class to which he belongs such a Secretary shall be permitted to draw the last drawn increment on a biennial basis provided that the Society is in profit and that the maximum number of increments so drawn shall not exceed three.

15. In case of efficiency bar, the Managing Committee of the Society shall allow the employees to cross the efficiency bar in case his/her work and conduct is found good provided the society is in profit.

16. Leave:

- (a) The authority competent to grant leave to the Secretary of the Society shall be the President of the Society.
- (b) The leave shall not be claimed as a matter of right. Leave granted may be cancelled and the Secretary may be called to duty if the exigency of service so requires.
- (c) The Secretary shall be eligible for the following kinds of leave:—
 - (i) Casual leave upto 12 days during the year.
 - (ii) Earned leave upto 30 days during the year.

Earned leave may be accumulated upto a maximum period of 90 days. Any accumulation in excess of 90 days shall lapse. Earned leave can be availed of at a time upto a period of 30 days.

17. Retirement:

- (a) The Secretary shall stand retired on attaining the age of 58 years. The date of retirement shall be the last date of the month in which the Secretary completes 58 years of age.

18. *Maintenance of Service Registers:*

Every society shall maintain a service register in the form prescribed by the Registrar for every employee to indicate his date of birth, qualifications, date of appointment, etc.

The Secretary shall authenticate the entries in the register and such register of the Secretary shall be authenticated by the President and kept in his custody.

Note.—The date of birth of the employees shall be that entered in the school leaving certificate. No other certification, horoscope etc. will be acceptable.

19. *Employees Welfare Fund:*

The Secretary shall be eligible for retirement assistance at the rates mentioned below:

The retirement assistance shall be payable to the Secretary after he has rendered continuous service for not less than five years:—

- (a) On his superannuation, or
- (b) On his retirement, or
- (c) Resignation, or
- (d) On his death or disablement due to accident:

Provided that the completion of continuous service of five years shall not be necessary where the termination of the employment is due to death or disablement:

Provided further that in the case of the death of the Secretary retirement assistance payable to him shall be paid to his nominee or, if no nomination has been made to his legal heirs.

Explanation.—For the purpose of this rule disablement means such disability as incapacitates an employee for the work which he was capable of performing before the accident or disease resulting in such disablement.

(2) For every completed year of service or part thereof excess of six months, he shall be eligible for the retirement assistance at the rate of one months pay subject to a maximum of Rs. 10,000/-.

(3) The Society shall maintain an Employees Welfare Fund and each year it shall allocate 10% of its net profit towards this fund. The retirement assistance shall be paid out of this fund subject to the approval of the managing committee and the Registrar.

(4) In case the contribution made by the society in para 3 falls short of the maximum amount due, the contribution shall be restricted to the actual amount in this fund. The society will however, be at liberty to pay upto the maximum of Rs. 10,000/- provided its resources so warrant and the Society is in profits.

(5) This fund shall be deposited in the Co-operative Bank to which the Society is affiliated and withdrawal from this fund would be in the manner stated in the proceeding paragraph.

20. *Provident Fund:*

(1) Subject to the provision of any law for the time being in force on the subject, a Society may establish the Provident Fund for its employees and after there has been carried to the Reserve Fund and Co-operative Education Fund and other funds, if any prescribed in the bye-laws of the Society, the necessary preposition of the net profits in any year may make such contribution not exceeding ten per cent of the remaining net profits.

(2) Such Provident Fund shall not be used in the business of the Society but shall be invested or deposited in the Co-operative Bank to which the society is affiliated.

(3) The amount of contribution that can be made by an employee in any month shall not exceed such sum as may be fixed by the general meeting subject to a maximum of 10 per cent of his monthly salary.

(4) The society may make such contribution every year to the Provident Fund of the employees as may be approved by the general meeting and the Registrar but such contribution shall not exceed the annual contributions made by the employees concerned.

(5) The interest accrued on the investment of the Provident Fund of the employees shall be credited in proportion to the balance standing to the credit of each account at the close of the preceding year.

21. *Payment of bonus:*

Subject to the provisions of any law for the time being in force on the subject, a society may set apart not more than ten per cent of its net profits for the payment of bonus to its salaried employees, if such payment is recommended by the managing committee and approved by the general meeting and the Registrar:

Provided that the amount of bonus should not exceed two months salary in an year.

22. *Prohibition of pecuniary transactions:*

(a) No Secretary shall have pecuniary transactions with individuals or institutions coming in contact with him in the course of his official duties or accept directly or indirectly, either on his own behalf or on behalf of any other person, any gift, gratuity or reward from any person with whom he may have to deal in his official capacity, provided that this clause shall not apply for the borrowings by an employee on the security of his deposits, savings, insurance policies or documents from other institutions and individuals.

(b) No Secretary of a Co-operative Society shall purchase directly or indirectly any property of a member of the society against his dues to the Society are sought to be recovered.

23. *Suspension:*

If the Secretary is arrested on any criminal charges the President of the society may order his suspension from the date of his arrest and for the payment of subsistence allowance to him during the period of suspension. If the Secretary is convicted and sentenced for any of the offences, his services shall be deemed to have been terminated from the date of conviction and in such cases it will not be necessary to give him any charge sheet. In case he is honourably acquitted he may be reinstated in the service of the society.

(b) Subsistence allowance shall be paid equivalent to half of the pay during the period of his suspension upto a maximum of one year after which period the disciplinary authority will review the case and take a decision regarding continuance or otherwise of the subsistence allowance and the rate at which will be paid.

24. *Disciplinary action:*

(a) The Secretary shall be awarded any one of the following punishment if found guilty on mis-conduct, apart from recovery of actual dues or damages caused by him to the Society.

(i) Warning.

(ii) Stoppage of increments for a period not exceeding one year without affecting future increments.

- (iii) With-holding of annual increment with or without cumulative effect.
- (iv) Termination.
- (v) Dismissal.
- (b) The Committee of the Society shall be the disciplinary authority to award punishment indicated above.
- (c) The term misconduct shall include any of the following acts on the part of Secretary:—
 - (i) Wilful damage or attempt to cause damage to the property of the Society.
 - (ii) Conviction by any court of law for any criminal offence involving moral turpitude.
 - (iii) Unauthorised disclosure or any attempt at disclosure information regarding affairs of the Society or any of members or any person connected with the Society.
 - (iv) Wilful disobedience of any lawful or reasonable order of the management or of the Co-operation Department.
 - (v) Failure to account for or concealment or misappropriation of cash or other property of the Society.
- (vi) Absence from duty without leave.
- (vii) Knowingly or wrongfully interfering or tampering the records of Society.
- (viii) Closing of office/shop of the Society other than permitted holidays without permission of management.
- (ix) Claiming or preferring any false claim.
- (x) Taking part or canvassing or otherwise interfering or using his influence in any election to the Central or State Legislature or Municipal Committees or Panchayats or other Local Bodies or the Society or any institution constituted under Himachal Pradesh State laws.
- (xi) Engaging in any other trade or occupation.
- (xii) Negligence in the performance of his duty.

N.B.—The above list is only illustrative and not exhaustive.

25. No punishment for misconduct shall be imposed on the Secretary unless he is proved guilty of misconduct in an enquiry conducted in the following manner:

- (i) The President shall serve to the Secretary a charge sheet in Form 'A' clearly stating the misconduct and the circumstances appearing against him and call for his explanation within a period of at least 15 days.
- (ii) If the Secretary accepts the charge, the Committee shall award suitable punishment to him. In case of denial, the Inspector, Co-operative Societies shall conduct the enquiry into the charges levelled against the Secretary.
- (iii) The Secretary shall be allowed to defend by himself and an outsider shall not be allowed to conduct the defence on his behalf.
- (iv) The Secretary shall be permitted to produce witness in his defence and cross examine any witness on whose evidence the charge rests.
- (v) The substance of the evidence shall be recorded and read over to the Secretary.
- (vi) The Inspector shall complete the enquiry and submit his report within two months to the Committee of the Society. The enquiry report shall include the statement of witness for and against the Secretary and the findings of the enquiry officer based on such evidence on each charge.
- (vii) On receipt of the enquiry report, the Committee of the Society shall examine the findings and pass necessary orders.
- (viii) The order of punishment shall be in writing and shall be issued under the signatures of the President of the Society or any other member of the Committee duly authorised and handed over to the Secretary.

26. *Appeal:*

Except in the case of awarding punishment of warning, an appeal shall lie against every order awarding punishment to the Secretary to the Assistant Registrar, Co-operative Societies incharge whose decision shall be final. Every appeal shall be presented to the appellate authority within thirty days of the date on which the order appealed against was communicated to him.

27. The Secretary shall not contest or canvass for any election to Central or State Legislatures or Municipal Corporation/Municipal Board, Panchayat/Co-operative Society or other elected bodies constituted under the Himachal Pradesh State laws.

28. *Prohibition of personal contracts etc:*

No Secretary of a Co-operative Society shall have any interest directly or indirectly, other than as an employee in:—

- (a) any contract made with the society; or
- (b) any property sold or purchased or leased by, or to the Society; or
- (c) any other transaction of the Society except as an investment made or as a loan taken from the Society or the provision of residential accommodation by the Society to any paid employees of the Society.

29. Interpretation of these rules as given by the Registrar, Co-operative Societies shall be final.

30. The Registrar may by an order in writing,—

- (a) exempt any society or class of societies from the application of any of the provisions of these rules, and
- (b) direct that any such provisions shall apply to such society to such extent as may be specified in the order.

FORM-A

[See rule 25 (i)]

To

.....
.....
.....

It has come to my notice that you have committed the acts as mentioned in the Annexure which amount to misconduct and they are punishable under Rule 24 of the Rules relating to the terms of employment and working conditions of the Secretaries of Primary Agriculture Credit Societies.

If the charges are not acceptable to, please submit your explanation in writing so as to reach within a week from the receipt of this notice. Please also note that in the event of your disputing the charges an enquiry will be held by the Inspector, Co-operative Societies.....
Block.....into the charges.

You are advised to remain present at the said enquiry and also furnish the names of your witnesses and produce the documents upon which you rely upon in your defence.

If you desire to inspect any papers connected with the basis of the charges, you can do so during working hours on any working day by making a request in writing.

Please note that if you do not remain present at the enquiry on the date and time intimated to you the enquiry will be proceeded *ex-parte*.

Date.....

President of the Society.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 28 जुलाई, 1986

संख्या पी0सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 15/86.—क्योंकि श्री लाल चन्द, वर्तमान प्रधान, ग्राम पंचायत खांगसर, जिला लाहौल स्पिति ने गत वर्ष जबकि वह ग्राम पंचायत गोंधला के प्रधान पद पर कार्यरत थे ने श्री रोशन लाल सुपुत्र श्री टर्शा राम, गांव खीनंग को मु0 6000/- रुपये से कम वार्षिक आय का झूठा प्रमाण-पत्र दिया जबकि उनके पिता श्री टर्शा राम उस समय राजकीय उच्च विद्यालय गोंधल में स्नातक अध्यापक के पद पर तैनात थे और उनकी वार्षिक आय मु0 19699/-रु0 के कम न थी।

क्योंकि इस प्रकार श्री लाल चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत खांगसर, झूठा प्रमाण-पत्र देने के दोषी पाये गये हैं।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री लाल चन्द प्रधान को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने का सहर्ष आदेश देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खांगसर के प्रधान पद से निष्कासित किया जाए। आपका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर जिलाधीश, लाहौल स्पिति के माध्यम से इस कार्य में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप अपने पत्र में कुछ नहीं कहना चाहते।

हस्ताक्षरित/-

उप-प्रचिद (पंचायत)।